Written by B4M
Wednesday, 27 July 2011 14:40

ये खबर हैरान करने वाली है लेकिन सच यही है कि राज्यसभा टीवी के आला अधिकारियों को परीक्षा और मैराथन इंटरव्यू कराने के बावजूद टीवी मीडिया से योग्य पत्रकार नहीं मिल रहे हैं. शायद यही कारण है कि 7 जून को आयोजित की गयी परीक्षा के बाद कुल स्वीकृत पदों से भी कम लोगों को साक्षात्कार के लि□ बुलावा भेजा गया. तो वहीं चयन सूची पर भी अब तक कोई सहमति नहीं बन पाना ये इशारा कर रहा है कि राज्यसभा टीवी चैनल के शुरू होने के पहले ही मतभेदों का सिलसिला शुरू हो गया है.

सूत्रों से मिल रही खबर के मुताबि□ चैनल में अभी से गुटबाजी शुरू हो गयी है. अभी चैनल लांच भी नहीं हुआ है कि नियुक्तियों को लेकर मतभेद उजागर हो रहे हैं. अपने पसंदीदा लोगों की इंट्री ना हो पाने के चलते □क खेमा नारा□ चल रहा है. अंदरूनी हालात कितने खराब हैं इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि चैनल में 80 फीसदी पदों के लि□ इंटरव्यू हो चुके हैं, बावजूद इसके चयन सूची जारी नहीं हो पाई है. कहा तो ये भी जा रहा है कि चयन सूची पर अभी तक आम सहमति नहीं बन पाई है. चैनल के लि□ कुल कितने पद स्वीकृत हु□ हैं ये नहीं बताया जा रहा है. चैनल के अंदरूनी सूत्रों की माने तो चैनल में उभर कर सामने आये दोनों गुटों में आपसी सहमति ना बन पाने के कारण □्यादातर पदों पर नियुक्तियां टाली जा रही हैं. हालांकि बाहर से "आल इज वेल" दिखाने की पूरी कोशिश चल रही है.

मीडिया के जानकार इस बात को लेकर भी हैरान हैं कि 22 जुलाई को हु□ □सोसि□ट प्रोड्यूसर के इंटरव्यू में मह□ 15 उम्मीदवारों को ही बुलावा भेजा गया. जिनमें से दो उम्मीदवार अनुपस्थित रहे थे. यानी सिर्फ 13 उम्मीदवारों का इंटरव्यू लिया गया, किसी भी उम्मीदवार को 5 मिनट से □्यादा वक्त नहीं दिया गया! जबकि असोसि□ट प्रोड्यूसर के लि□ स्वीकृत पदों की संख्या 25 से □्यादा बताई जा रही है. ऐसे में नियमों को ताक़ पर रख कर मह□ 13 उम्मीदवारों का ही इंटरव्यू लेना ये इशारा कर रहा है कि दाल में कुछ काला है. गौरतलब है कि उम्मीदवारों के पूछे जाने के बावजूद भी चैनल के आला अधिकारियों ने अभी तक इस बात को उजागर नहीं किया है कि चैनल के विभिन्न विभागों में कुल स्वीकृत पदों की संख्या कितनी है?

दिलचस्प बात ये है कि मैराथन इंटरव्यू के बावजूद जिन चुने हु□ लोगों को नियुक्ति पत्र दि□ ग□, उनमें से अधिकाँश पहले से ही इसकी घोषणा कर चुके थे. तो ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो अपनी ऊंची पहुँच का हवाला देकर जल्द ही नियुक्ति पत्र पाने का दावा कर रहे हैं. ऐसे में चयन सूची की गोपनीयता पर सवालिया निशान लग गया है. हैरानी वाली बात ये भी है कि राज्य सभा टीवी में विभिन्न पदों पर देश भर के ह□ारों अनुभवी टीवी पत्रकारों ने आवेदन किया था. यहाँ तक कि आयोजित परीक्षा के दौरान ब□ी संख्या में प्रमुख खबरिया चैनलों के पत्रकार जुटे थे. बावजूद इसके राज्यसभा टीवी के अधिकारियों को अपने चैनल के लि□ योग्य पत्रकार नहीं मिल पा□. इसलिये चैनल में कम से कम पदों पर ही नियुक्ति की जा रही है. और बाकी पदों को भविष्य में योग्य उम्मीदवारों के आने का इंत□ार है.